



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2007/कार्तिक 14, 1929

No. 335]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2007/KARTIKA 14, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2007

सं. 79 (आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/पीएन/एचबीपी/एम-08/  
पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. "पोत-लदान बिलों और/अथवा बैंक वसूली प्रमाण-पत्र की खो गयी ईपी प्रति के मद्दे मामलों पर विचार" से सम्बंधित एक नया पैराग्राफ 4.30क को पैराग्राफ 4.30 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जायेगा:

4.30क जिन मामलों में पोत-लदान बिल की मूल ईपी प्रति/मूल बीआरसी खो गयी है, ईओडीसी हेतु आवेदन, अग्रिम प्राधिकार पत्र/बीएफआईए स्कीम के तहत किसी बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उन मूल दस्तावेजों के बदले निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए :-

क. सीमाशुल्क प्राधिकारी/बैंक द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज के मूल के बदले डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रति।

ख. बचायी गई शुल्क की राशि के 1 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसे दस्तावेज के खो जाने और इस बारे में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

ग. दस्तावेज के खो जाने और बाद में मिलने पर

उसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को तुरंत सौंपने की बचनबद्धता का शपथ-पत्र।

घ. खो गए पोत-लदान बिलों/बीआरसी के लिए प्राप्त/अनुमत शुल्क मुक्त आयात हकदारी के मद्दे सरकार को किसी वित्तीय हानि, यदि हुई है तो, क्षतिपूर्ति करने के लिए निर्यातक इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। सीमा शुल्क प्राधिकारी, बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता के पृष्ठांकन के बिना अथवा हस्तांतरणीयता के पृष्ठांकन के बाद बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता की विमुक्ति या निकासी की अनुमति से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पोत-लदान बिल के मद्दे कोई दोहरा लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

तथापि, मूल पोत लदान बिल के बदले पुनःनिर्मित पोत-लदान बिल प्रस्तुत करने के मामले में, उपरोक्त ख., ग. और घ. की शर्तें लागू नहीं होंगी।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या-79 दिनांक 2-1-2006 में क्रम संख्या 1 (v) में आने वाले शब्द 'मॉडवैट' को संशोधित करके मॉडवैट/सेनवैट पढ़ा जाएगा।

3. पैराग्राफ 5.18.6 के बाद एक नया पैराग्राफ 5.18.7 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

5.18.7—ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों हेतु पूर्वोक्त प्रावधान 1-4-2007 को अथवा उसके बाद जारी प्राधिकार पत्रों के लिए लागू होंगे। तथापि, 1-4-2007 से पहले जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आरई-2006) के अध्याय-5 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th November, 2007

No. 79 (RE-2007)/2004—2009

**F. No. 01/94/180/PN/HBP/AM-08/PC-1.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Handbook of Procedures (Vol-1):

1. A new paragraph 4.30A related to “consideration of cases against lost EP copy of the Shipping Bills and/or Bank Realisation Certificate” shall be added after the paragraph 4.30 as follows:—

4.30A. In case where Original EP copy of Shipping Bill/original BRC has been lost, request for EODC, No BG/LUT condition under Advance Authorisation/DFIA scheme or endorsement of transferability under DFIA scheme can be considered subject to submission of following documents in lieu of those original documents:

- (a) A duplicate/certified copy of concerned document issued by Customs Authority/Bank in lieu of original;
- (b) An application fee equivalent to 1% of duty saved amount. However, no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;

(c) An affidavit by exporter about loss of document and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently;

(d) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss, if any, on account of duty free import entitlement availed/allowed against lost Shipping Bills/BRC. Customs Authority, before allowing redemption of BG/LUT or clearance after endorsement of No BG/LUT condition or endorsement of transferability, shall ensure that no double benefit against such shipping bill has been availed. However, in case of submission of reconstructed copy of shipping bill in lieu of original shipping bill, conditions at (b), (c) and (d) above shall not be applicable.

2. The word MODVAT appearing at Sl. No. 1 (v) in PN No. 79 dated 2.1.06 shall be amended to read as MODVAT/CENVAT.

3. A new paragraph 5.18.7 shall be added after paragraph 5.18.6 to read as follows:

5.18.7—The aforesaid provisions for Clubbing of EPCG Authorisations shall be applicable for authorisations issued on or after 1-4-2007. However, EPCG authorisations issued prior to 1-4-2007, shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP, Vol-1 (RE - 2006).

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and  
ex-officio Addl. Secy.